नशा मुक्त भारत आन्दोलन

Movement for Intoxicant Free India

नई दिल्ली,
25 अगस्त, 2016

प्रेस विज्ञप्ति

दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में नशा मुक्त भारत आन्दोलन की प्रेस कांफ्रेन्स को संबोधित करते हुए स्वामी अग्निवेश (जदयु) भृगु फाउन्डेशन के गोस्वामी सुशील जी महाराज, साँई मियां मीर इन्टर नेशनल फाउन्डेशन से सरदार परमजीत सिंह चंडोक, कुलदीप सिंह भोगल एवं जीमयत उलेमा–ए–हिंद के महासचिव मुफ्ती अब्दूर राजिक, डा० सुनीलम आदि के संयुक्त तत्वावधान में कहा गया कि संविधान की अनु० 47 को पूरे भारत में लागू कराने हेतु हम प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करने का आग्रह करेंगे जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी हेतु निर्णय लिया जा सके तथा राज्यों को होने वाले राजस्व हानि का 50 प्रतिशत का भुगतान 5 वर्षो तक करना चाहिए जैसा कि 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने वादा किया था।

हम उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया के कथन का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी लागू होने पर दिल्ली प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी लागू करने का वादा किया है।

इस बीच शराबबंदी के लिए मोहल्ला सभा को जिम्मेदार ठहराने की अपेक्षा बेहतर होता केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर पूरे दिल्ली में जनमत संग्रह कराती। पूर्व में उन्होंने जनमत संग्रह द्वारा सरकार चलाने का वादा भी किया था। हमें विश्वास है कि प्रचण्ड बहुमत से दिल्ली की जनता शराबबंदी को अपना समर्थन देगी और शराब की दुकानो को बंद करने पर मुहर लगाएगी। क्या ही अच्छा होता कि केजरीवाल शराबबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के साथ मंच साझा करते और शराब की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अवैध आवाजाही को रोकने के लिए देशभर में शराबबंदी लागू करने की मांग भी उठाते।

मैं दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी दर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ। किन्तु इससे भी कहीं अधिक जरूरी है शराब की दुकानों का बंद होना। शराब की दुकानें खुली रहेंगी तो मजदूर दिनभर की हाड़तोड़ मेहनत का पूरा लाभ नहीं उठा पायेगा क्योंकि शाम को वह बढ़ी कमाई ठेके पर बरबाद कर देगा। दिल्ली को अपराधों की राजधानी बनाने में शराब एवं नशे के कारोबार की बड़ी भूमिका है। वर्ष 2012 के बाद से महिला अपराधों में तीन गुना तक की वृद्धि देखी गयी है।

दिल्ली प्रदेश पहले से ही बहन–बेटियों के लिए असुरक्षित होती जा रही है, ऊपर से केजरीवाल सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष शराब की दुकानें खुलवाना अफसोसजनक है। शराब सेवन से किडनी व लीवर सम्बन्धी भयानक बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा परिवार को और पीछे धकेलने का कार्य करती है। शराब से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी मनगढ़न्त कहानी ही है क्योंकि यदि इससे 100रू. राजस्व की प्राप्ति होती भी है तो उसके बदले सरकार को अपराध नियंत्रण व बीमारियों के इलाज में 124 रू. अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं।

अतः मेरी अपील है कि यथाशीघ्र केजरीवाल सरकार दिल्ली में पूर्ण शराबबंदी को लागू करें और केन्द्र सरकार, बिहार, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों के साथ मिलकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाने में पहल करें।

दलसिंगार
मीडिया कोऑर्डिनेटर
मो०.9871382237